EDITORIAL

Deluge in God's Own Country

We salute the people of Kerala, the brave hearts who faced their worst disaster in their life time. Nature thro Water acted as a destructive weapon in its great fury. Fortunately sometimes the natural disasters make our society to act in cohesion and unison. We all witnessed the exhibition of highest human qualities like compassion, courage and hope of redeeming. Shri Ram Nath Kovind , President of India has acknowledged the grit and resilience of the people of Kerala in coming together in that trying hour.

The entire state of Kerala was ravaged by the unprecedented heavy rain fall and flood. The immediate estimate says that the loss of valuable lives touched 357. The floods destroyed roughly 906,400 hectares worth of crops. The cost to the state and its people stands at a staggering Rs 19,500 crore.

As per the report of NDMA(National Disaster Management Authority) 6.50 lakh people have been taken to shelter. As per media reports it may be more than 12 lakh. The lakhs of relocated people should be brought back to their respective areas after paying attention in repairing the infrastructure like roads, electricity, and other connectivity. Their lost home should be set right to house them back. The NCMC (National Crisis Management commitee) has directed the concerned authorities for the emergency supplies of food, drinking water, medicines and restoration of essential services. The rescue work done by the army, air force, local volunteers, fishermen are commendable.

The state Govt feels that 20000 crores may be needed to restore the infrastructure and even day to day life of Kerala. .The Chief Minister shri Pinarayi Vijayan with Prime Minister Shri Modi undertook aerial survey. The CG government announced 500 crore assistance. The CM has narrated the situation as the worst floods in a century and requested at least 2000 crore as immediate relief. Shri Rahul Gandhi has preferred his appeal that the Central Govt should declare it as a national disaster.

Railways have announced that the relief materials would be transported in free of cost. They have made their own help desks. Civil aviation department has been working round the clock to help the people affected. The Centre has undertaken a special evacuation plan by trains over the weekend, taking an estimated 25,000 migrated labourers to their home states.

As usual, the best operator in all calamities is our BSNL . This time also in Kerala we have tried our best for seamless services. BSNL has announced its unlimited free calls and data services along with SMS services. AirTel and Reliance Jio also followed the footpath of BSNL and offered some free services.

Bunch of recommendations to the central government was given In 2011 by the Gadgil Committee about ecologically-fragile regions in the Western Ghats. They found the highest number of vulnerable zones in Kerala. The other main causes are quarrying, mining, illegal repurposing of forests and high-rise building constructions, all were man-made. One report from BBC hinted that Kerala did not get early flood warning from the central water commission and there are no forecasting sites in Kerala, only having flood monitoring sites. Dam Management Experts are telling that filling reservoirs before the end of monsoon is an invitation to disaster quoting Idukki dam was already full before the rains.

Tourism sector is going to face a big crisis. The toll was estimated at 30000 crore. Tourism accounts 10 % of the state's GDP and it employs 14 lakh people. Reports are coming about the worst affected paddy and rubber, coconut main crops of the state. Kerala is one of the top ranking states for consumer durables. Most of the households have the assets like Pucca house, electricity, mobile, AC, Refrigerator, TV, washing Machine, Vehicles. People living in the worst affected areas lost all these assets.

Supreme Court Judges to ordinary workers in small town have all started extending their support. The legislatures have started donating their one month salary.. Our Chq has decided to extend its helping hand to the affected people of Kerala. The circle unions are hereby advised to approach our employees and get maximum amount possible for Kerala relief and send the same to Chq at the earliest. Let us embrace Kerala, the lovable land.

संपादकीय

भगवान के देश में जल प्रलय

हम केरल के बहादुर दिल जन समुदाय को सलाम करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में विभत्स आपदा का सामाना किया। प्रकृति ने अपने प्रचण्ड क्रोध को शांत करने के लिए जल प्रवाह को विनाशकारी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। प्रकृति अपनी विपदा द्वारा कभी–कभी हमें एकजुटता की पाठ पढ़ाती है तथा हमेशा एकजुट रहने की शिक्षा देती है। इस विभत्स विभिषिका में हम सबों ने करूणा, त्याग, साहस, एवम् दूसरे को बचाने की आशा जैसी मानव गुणों की उच्चतम प्रवृति देखी। भारत के राष्ट्रपति ने इस संकट की घड़ी में लोगों के एकजुटता में लचीलापन की ओर इंगित किया है। केरल राज्य अप्रत्यासित बारिस एवं बाढ़ से तबाह हो गया है। तत्कालिक अनुमान है कि पांच सौ से ज्यादा मूल्यवान मानव जीवन को इस त्रासदी ने निगल लिया है। बाढ़ ने लगभग 906400 हेक्टेयर फसलों को नष्ट कर दिया है। राज्य एवं उसके लोगों की क्षति 19,500 करोड़ अनुमानित की गई है।

राष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रिपोर्ट के अनुसार 6.50 लाख लोगों को आश्रय में ले जाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह आकलन 12 लाख तक की है। सड़क, बिजली, रेल, टेलीकाम जैसे बुनियादी ढांचों को पुनः निर्माण के बाद लाखों लोगों को उनके घर वापसी की व्यवस्था करनी है। उनका खोया आशियाना उन्हें वापस मिलना चाहिए। नेशनल आपदा प्रबंधन समिति ने संबंधित अधिकारियों को, भोजन, पेयजल, दवाईयां आदि आवश्यक जीवन रक्षक समानों का आपातकालीन आपूर्ति के लिए निर्देशित किया है। थल सेना, वायु सेना, स्थानीय स्वयं सेवकों, मछुआरों, द्वारा किए गए बचाव कार्य सराहनीय हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि केरल के बुनियादी ढांचे को बहाल करने और केरल के दिन–प्रतिदिन के दिनचार्य को व्यस्थित करने के लिए बीस हजार करोड़ रूपये की आवश्यकता पड़ेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं श्री पिनारायी विजयन ने हवाई सर्वेक्षण करके विनाश का आंकलन किया है। केन्द्र सरकार ने पांच सौ करोड़ रूपये की सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस स्थिति को शताब्दी के बाद बाढ़ जनित सबसे वीभत्स आपदा बताया है और कम से कम बीस हजार करोड़ रूपये तत्कालिक सहायता की मांग की है। श्री राहुल गांधी ने अपने अपील को प्राथमिकता देते हुए केन्द्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आग्रह किया है। रेलवे ने राहत सामग्री मुफ्त ढुलाई करने की घोषणा की है। उन्होंने अपनी सहायता डेस्क बनाई है। नागरिक उड्डयन विभाग सहायता के लिए दिन–रात कार्यरत है। केन्द्र ने सप्ताहांत में रेलों द्वारा एक विशेष निकासी योजना शुरू किया है, जिससे पचीस हजार से अधिक प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य में भेजे जा सकेंगे।

हमेशा की तरह सभी राष्ट्रीय आपदाओं में अग्रणी भूमिका अदा करने वाली हमारी कम्पनी बीएसएनएल ने केरल की आपदा में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। बीएसएनएल ने न केवल एसएमएस अपितु असिमिति फ्री कॉल एवं फ्री डाटा प्रदान कर पीड़ितों की सेवा की है। प्रारंभ में निजी दूरसंचार संचालक लापता हो गए पर बाद में बीएसएनएल का अनुसरण करते हुए एयरटेल एवं रिलायंस जियों ने भी कुछ पहल की है।

परिस्थितियों के रूप में नाजुक क्षेत्रों में होने वाले नुकसान की समीक्षा के उपरान्त सन् 2011 में गाडजिल समिति ने केन्द्रसरकार को कुछ सिफारिशें भी की। समिति ने केरल में परिस्थित आपदा का सबसे कमजोर जोन का आंकलन किया था। उन्होंने इसके कारणों में खदान, खनन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई एवं निर्माण कार्य, अवैध निर्माण एवं उच्च वृद्धि भवन निर्माण, सभी मानव निर्मित हैं।

बी.बी.सी. ने एक रिपोर्ट में संकेत दिया कि केरल को केन्द्रीय जल आयोग से प्रांरभिक बाढ़ चेतावनी नहीं दी गई और केरल में कोई पुनर्वानुमान साइट भी नहीं हैं, केवल बाढ़ निगरानी साइटें हैं बांध प्रबंधन के लोग बता रहे है कि मानसून के समाप्ति से पहले जलाशरयों का भर जाना आपदा को निमंत्रण देने के बराबर है और इडुबकी जलाशय मानसून के पहले ही भर चुका था।

केरल में पर्यटन से एकल घरेलू उत्पाद का 10% आय होती है। पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसे 30,000 करोड़ के घाटे का अनुमान है। पर्यटन केरल में 14 लाख लोगों को रोजगार देती है। सबसे खराब रिपोर्ट धान, नारियल एवं रबड़ की फसलों की बर्बादी का मिल रहा है। केरल उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन करने वाले शीर्ष रैकिंग वाले राज्यों में से एक है। केरल में अधिकांश पक्का मकान ओर उनमें टी.वी., रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, बिजली उपकरण, मोबाइल, ए.सी, वाहन आदि उपलब्ध हैं। इन सशस्त सम्पत्तियों का विनाश हो चुका है, जिसे फिर से अर्जित करना होगा।

छोटे शहरों के श्रमिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायधीशों ने समर्थन किया है, विधायकों ने अपना एक माह का वेतन दान किया है। हमारे संघ के मुख्यालय ने भी अपने परिमंडलों से केरल के सहायतार्थ आगे बढ़कर दान देने की आग्रह किया है। बीएसएनएल कर्मियों ने अपना एक दिन का वेतन देने की कवायद की है। बढ़ों साथियों, हाथ बढ़ाओं और अपने प्यारे केरल के प्यारे भाई–बहनों को गले लगाओं।